

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 373 राँची, सोमवार,

15 चैत्र, 1938 (श॰)

4 अप्रैल, 2016 (ई॰)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

.. 28 मार्च, 2016

विषय: "मिलिक (मुस्लिम)" को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनूसूची-II) के रिक्त क्रमांक-45 पर शामिल करने के संबंध में।

संख्या-14/जा0नि0-03-03/2016 का॰ **2574--**झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह कि "आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-9(1) के अधीन "मलिक (मुस्लिम)" जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-।।) में अन्तिम प्रवृष्टि में "मलिक (मुस्लिम)" जाति को शामिल करने का सलाह देती है" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-।।) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय:-

समावेशन(अनुसूची-॥)

(i) मलिक (मुस्लिम) जाति को क्रमांक-44 के बाद रिक्त क्रमांक-45 पर दर्ज किया जाय।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार, सरकार के सचिव।
